मुख्यमंत्री ने टीकाराम जूली के गांव पहुंच कर शोक जताया

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की स्व. माताजी के चित्र को पुष्प अर्पित किए

कोटपूतली-बहरोड़/जयपुर, 5 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को कोटपूतली-बहरोड़ की माढ़ण तहसील के ग्राम काठूवास पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने स्व. चलती देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।

इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह, सांसद व प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और विधायक देवी सिंह शेखावत सहित, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को कोटपूतली-बहरोड़ के ग्राम काठूवास में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह, सांसद व प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद थे।

'खामनेई का उत्तराधिकारी भी मारा जाएगा'

तेहरान/वाशिंगटन/तेल अवीव, 05 मार्च। ईरान पर अमेरिका-इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान के तहत किए गए आक्रमण में अब तक मिली सफलता की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अब ईरान के अगले नेता की भी मौत हो सकती है। इस बीच इजराइल ने ईरान के एक बड़े नौसेना के ठिकाने पर विस्फोट किया है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि श्रीलंका में युद्धपोत पर किए

- **अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले की कार्यवाही पर खुशी जताते हुए कहा**

गए हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। इस बीच, ईरान के बंदर अब्बास में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) नेवल बेस के पास जोरदार धमाके हुए हैं।

ईरान इंटरनेशनल समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि ईरान के साथ लड़ाई बढ़ ने पर अली खामेनेई के होने वाले वारिस मारे जाएंगे। उधर, इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने कहा कि उसने ईरान में एक महत्वपूर्ण मिलिट्री कंपाउंड के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन पूरा किया है। आईडीएफ ने इस कंपाउंड में स्थित ईरान की सैन्य सुरक्षा के कई महत्वपूर्ण मुख्यालयों को नुकसान पहुंचाया।

स्व. अजित पवार के बेटे पार्थ राज्यसभा जाएंगे

राज्यसभा में पवार परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने की पूरी संभावना है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मार्च। इस बार महाराष्ट्र से पवार परिवार के दो सदस्य राज्यसभा सांसद बनने वाले हैं। वे अलग-अलग पार्टियों, अलग-अलग राजनीतिक खेमों और अलग-अलग पीढ़ियों से आते हैं। पवार परिवार के मुखिया शरद पवार (85) संसद के उच्च सदन में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। वहीं शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पहली बार सांसद बनने की तैयारी में हैं।

दरअसल, कुछ समय तक राज्यसभा में तीन पवार भी रह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जो पार्थ की मां हैं, ने अभी तक राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दिया है।

मौजूदा स्थिति के अनुसार, 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद संसद में पवार परिवार के तीन सदस्य होंगे-राज्यसभा में शरद पवार और पार्थ पवार तथा लोकसभा में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले।

इस वर्ष महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटों पर चुनाव होने जा रहा है।

- **पार्थ की मां और स्व. अजित की पत्नी सुनेत्रा ने अभी तक राज्यसभा सदस्यता नहीं छोड़ी है और अजित के चाचा शरद पवार एक बार फिर एमवीए के टिकट पर राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं।**
- **लोकसभा में शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले पहले से ही मौजूद हैं, इस प्रकार पवार परिवार एक मात्र ऐसा खानदान है जिसके दो से तीन सदस्य संसद में देखे जाएंगे।**

राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट देते हैं, और 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के कारण, इन सात सीटों में से छह उसके खाते में जाने की संभावना है।

इनमें भाजपा को चार सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को एक सीट और अजित पवार की एनसीपी को एक सीट मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार विपक्ष के लिए केवल एक सीट बचती है।

कुछ समय पहले कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) दोनों ने राज्यसभा सीट पर दावा किया था। बाद में शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे के निवास पर जाकर उनकी पार्टी का समर्थन मांगा। जब यह स्पष्ट हो गया कि वरिष्ठ नेता तीसरी बार राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस ने भी, हाई कमान की सलाह पर, शरद पवार के नाम पर सहमति दे दी।

पार्थ पवार (35) एनसीपी प्रमुख अजित पवार के बेटे हैं, जिनकी इस साल जनवरी में एक दुखद विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

अजित पवार की मृत्यु से पहले उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद बन गई थीं। दुर्घटना में अजित की मौत के बाद सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। उनके इस्तीफे के बाद सीट खाली होने पर एनसीपी नया उम्मीदवार नामित करेगी।

महाराष्ट्र में शरद पवार कैसे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रणनीतिकार की भूमिका निभा सकते हैं।

लेकिन एक व्यावहारिक मुद्दा था, जिसे सुलझाना था।

कांग्रेस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि एनसीपी के दोनों गुट आपस में विलय न करें और शरद पवार एनडीए में शामिल न हों। ऐसा होने पर कांग्रेस की भारी किरकिरी होती।

राज्य कांग्रेस नेताओं ने एनसीपी नेताओं से यह बयान दिलवाया कि दोनों एनसीपी के बीच विलय की संभावना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जयंत पाटिल ने एनसीपी (एस.पी.) की ओर से मीडिया को बयान जारी कर कहा कि अजित पवार के निधन के बाद से दोनों एनसीपी के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है।

जब यह साफ हो गया कि दोनों एनसीपी का विलय नहीं होगा, तब कांग्रेस ने शरद पवार की राज्यसभा

- **समर्थन के बदले में शिवसेना को महाराष्ट्र विधान परिषद की सीट दी गई जो उद्धव को जाएगी। इस सीट को जीतने के लिए 37 विधायकों की जरुरत है और उद्धव के पास 29 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16 और पवार के पास 10 विधायक हैं। इन सभी के समर्थन से उद्धव की जीत पक्की हो गई है।**

उम्मीदवारी पर सहमति दे दी।

शिवसेना ने अपनी सीट त्याग दी और प्रियंका चतुर्वेदी ने एक भावुक पोस्ट में कहा: "उन सभी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने मेरा साथ दिया और प्रार्थना की... ये संदेश मुझे जहां भी रहूं, फोकस्ड रहने और कड़ी मेहनत करने में मदद करेंगे।

गठबंधन, विधान परिषद में शिवसेना (यू.बी.ए.) को एक सीट देगा, जो उद्धव ठाकरे को मिलेगी।

प्रत्येक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। एम.वी.ए. के पास 46 विधायक हैं, जिनमें उद्धव सेना के 29, कांग्रेस के 16 और शरद पवार गुट के 10 विधायक हैं। इसलिए वे निश्चित रूप से एक सीट जीत सकते हैं।

सत्तारूढ़ महायुति के पास 288 सदस्यीय विधानसभा में 228 विधायक हैं, जिसका मतलब है कि उसके छह उम्मीदवार जीतेंगे। इन छह सीटों में से एक रामदास अठावले को मिलेगी, जो केन्द्र में मंत्री भी हैं।

नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन भरा

पटना, 05 मार्च। बिहार की राजनीति में गुरुवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के

- **भावुक समर्थकों ने नीतीश के आवास के बाहर प्रदर्शन किया**

नितिन नबीन और रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के उपेन्द्र कुशवाहा तथा शिवेश कुमार ने भी अपने नामांकन दाखिल किये।

सभी उम्मीदवारों ने बिहार विधानसभा परिसर स्थित विधान सभा कार्यालय प्रकोष्ठ में सचिव की उपस्थिति में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र जमा किए। नामांकन दाखिल करने के दौरान राजनीतिक माहौल काफी सक्रिय दिखाई दिया और गठबंधन के कई बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे।

नामांकन दाखिल होने के साथ ही, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में और भी हलचल देखने को मिल सकती है।

इधर बिहार की राजनीति में गुरुवार को उस समय भावुक और तीखे दृश्य देखने को मिले, जब बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुट गए।

फर्जी पट्टे जारी करने पर अजमेर नगर निगम के चार अधिकारी एपीओ

अजमेर के कांग्रेस नेताओं ने पिछले 5 वर्षों में जारी सभी पट्टों की जांच की मांग की

अजमेर, 5 मार्च (कासं)। अजमेर नगर निगम में फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में डिप्टी कमिश्नर सहित चार अधिकारियों के एपीओ होने के बाद सियासत गरमा गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार जयपाल सहित, नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम में नियमों को दरकिनार कर फर्जी और अवैध तरीके से पट्टे जारी किए गए। यह पूरा प्रकरण प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं, बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि को सरकार द्वारा अवाप्त (अधिग्रहित) किया जा चुका था, उसका पहले नक्शा स्वीकृत कर दिया गया और शिकायत सामने आने के बाद उसे निरस्त किया गया। यह कार्रवाई खुद साबित करती है कि प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा का नगर निगम बोर्ड अब तक का 'सबसे भ्रष्ट' बोर्ड रहा है। उनके अनुसार, बोर्ड के संरक्षण में कर्मचारियों द्वारा नियमों की अनदेखी कर अवैध पट्टे जारी किए गए। धर्मेन्द्र राठौड़ और डॉ. जयपाल ने कहा कि नगर निगम बोर्ड हर मोर्चे पर विफल रहा है। चाहे सफाई व्यवस्था का मुद्दा हो, पट्टों का वितरण हो या जनता को राहत देने का मामला, हर क्षेत्र में भाजपा बोर्ड असफल साबित हुआ है। नेताओं ने कहा कि निगम के कर्मचारी बोर्ड के संरक्षण में भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिसके चलते शहर की व्यवस्था चरमरा गई है और

- **कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जिस भूमि को सरकार द्वारा अवाप्त किया जा चुका था, उसका निगम अधिकारियों ने नक्शा स्वीकृत कर दिया था। शिकायत होने के बाद उसे निरस्त किया गया। यह कार्यवाही साबित करती है कि प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुईं।**

जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है।

कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि भाजपा बोर्ड के कार्यकाल के पिछले पांच वर्षों में जारी किए गए सभी पट्टों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि केवल अंतिम छह महीनों के ही नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल के दौरान जारी पट्टों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर सख्त रोक लग सके। अधिकारियों के एपीओ होने के बाद, अब यह मामला राजनीतिक ही नहीं, प्रशासनिक जवाबदेही का भी बड़ा मुद्दा बन गया है।

बुलैट ट्रेन प्रोजैक्ट की लागत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मूल अनुमानित लागत 1,08,000 करोड़ रुपये का लगभग 53 प्रतिशत खर्च होने के बाद, यह परियोजना अब मध्य-कालीन संशोधन की स्थिति से गुजरती प्रतीत हो रही है। नई दिल्ली ने जापान द्वारा प्रस्तावित ई10 शिंकानसेन संस्करण को खरीदने में अनिच्छा जताई है, जिसकी लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके बजाय सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल)" को ऐसे ट्रेनसेट बनाने का अनुबंध दिया है, जो अधिकतम 280 किमी प्रति घंटा की गति से चलेंगे (जबकि शिंकानसेन की गति 320 किमी प्रति घंटा है)।

सिग्नलिंग अनुबंध भी जापान के बजाय "डीआरए-सीमेंस" के एक कंसोर्टियम को दिया गया है, जो ईसीटीएस-2 सिस्टम तैनात करेगा, जबकि जापान ने कोएक्सियल लीकी केबल सिस्टम की पेशकश की थी।

इसके अलावा, एनएचएसआरसीएल को महाराष्ट्र के ठाणे क्रीक के पास पानी के नीचे सुरंग बनाने के लिए आवश्यक 13 मीटर टनल बोरिंग मशीन (टी बी एम) हासिल करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये मशीनें जर्मन कंपनी "एच के" ने चीन स्थित अपने संयंत्र में बनाई थीं। शुरूआत में भारत नहीं पहुंच सकी थीं, क्योंकि इन्हें भारत लाने वाले जहाजों को दक्षिण चीन सागर में चीनी कस्टम अधिकारियों ने रोक लिया था। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के हस्तक्षेप के बाद, चीन सरकार ने अंतत: अपने बंदरगाह के माध्यम से इस सामान को भेजने की अनुमति दी, लेकिन सूत्रों के अनुसार मशीनों के कई महत्वपूर्ण पुर्जे गायब हैं। इसी कारण ये टी बी एम फिलहाल मुंबई बंदरगाह पर बेकार पड़ी हुई हैं।

लद्दाख के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं किया गया है। राजनीतिक विश्लेषक इस इस्तीफे को एक महत्वपूर्ण घटना मान रहे हैं। उनका मानना है कि इसका असर लद्दाख के प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ सकता है। कविंदर गुप्ता के इस्तीफे के बाद लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना को नया उप राज्यपाल बनाया गया है, जो अभी तक दिल्ली के उप राज्यपाल थे।

मोज़तबा को खामनेई का उत्तराधिकारी बनाने पर सहमति बनी

तेहरान, 05 मार्च। अमेरिका-इजराइल के हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में उनके दूसरे बेटे मोजतबा खामेनेई के नाम पर सहमति बन गई है। इसे लेकर पवित्र शहर कोम में 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञों की सभा) में मतदान हो चुका है।

- **मोज़तबा ईरान के हाल ही में मारे गए सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई के दूसरे पुत्र हैं**

ईरान इंटरनेशनल अखबार ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स गुरुवार को एक आपात सत्र में मोजतबा खामेनेई को आधिकारिक नेता के तौर पर घोषित करेगी। यह सत्र ईरान इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट के दो दिन बाद आहूत किया गया है, जिसमें कहा गया था कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के दबाव में मोजतबा खामेनेई को अगला नेता चुना है।

तृणमूल के चार प्रत्याशियों ने राज्यसभा का पर्चा भरा

कोलकाता, 05 मार्च। राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने गुरुवार को आधिकारिक रूप से अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। पार्टी की ओर से अभिनेत्री कोएल मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी, पूर्व पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार और मंत्री बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाया गया है।

ईरान के आकाश पर अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। इसलिए भारत ने दूसरा रास्ता चुना। सोवियत मिग-21, मिग-23, मिग-29, और सुखोई-30एमकेएल, जो आज भी भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। साथ ही ब्रिटिश-फ्रेंच जैगुआर, फ्रांसीसी मिराज-2000 और ब्रिटिश हॉकर हंटर विमान। । पीढ़ी दर पीढ़ी भारत ने शांतिपूर्वक और सोच-समझकर ऐसी वायुसेना बनाई जो वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं थी।

शीत युद्ध के खत्म होने के बाद माहौल बदला और1990 के दशक में नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच रिश्तों में गर्मजोशी आई। दो बड़े लोकतंत्र, जिनकी चिंताएं भी मिलती-जुलती थीं और आर्थिक संबंध भी बढ़ रहे थे। कुछ समय के लिए लगा कि एक नई शुरुआत हो रही है। फिर मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया।

क्लिंटन प्रशासन की प्रतिक्रिया तुरंत आई। अमेरिका ने जल्दी ही प्रतिबंध लगा दिए। तकनीकी सहयोग रोक दिया गया। कूटनीतिक रिश्तों में अचानक ठंडापन आ गया। वॉशिंगटन का संदेश साफ था। अगर आप यह फैसला अपने तरीके से लेते हैं, तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। भारत ने वह कीमत चुकाई, लेकिन उसे कभी भूला नहीं।

1998 की उस घटना ने भारत की रणनीतिक सोच में गहरी छाप छोड़ दी, एक तरह का संदेह और अविश्वास पैदा कर दिया। बाद की सरकारों ने इसे कम करने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी रहीं, लेकिन पूरी तरह खत्म

- **भारत ने बाकी और कई हथियार खरीदे अमेरिका से, पर फाइटर हवाई जहाज नहीं। भारत ने पाकिस्तान व टर्की की स्थिति देखी थी, अमेरिका ने दोनों देशों को आधुनिक फाइटर जहाज दिये, पर इन दोनों देशों पर स्पेयर पार्ट्स न सप्लाई करने का विकल्प अपने पास रखा। जब भी कोई नीतिगत मतभेद हुआ, अमेरिका ने टर्की व पाकिस्तान के स्पेयर पार्ट्स न देने की धमकी दी और धमकी क्रियान्वित भी की। भारत अपने आपको कभी भी इस स्थिति में नहीं देखना चाहता था। अतः अमेरिका से फाइटर हवाई जहाज न खरीदने का दृढ़ संकल्प लिया।**

नहीं कर पाईं।

आज आंकड़ों में यह साफ दिखाई देता है। भारत ने अमेरिका से सी-17 ग्लोबमास्टर भारी परिवहन विमान, सी-130जे सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान, हिंद महासागर में पनडुब्बियों की खोज और लंबी दूरी की निगरानी के लिए पी-81 पोसीडॉन, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक, भारी हेलीकॉप्टर और तेजी से मिसाइल दागने वाले एमक्यू-9बी प्रीडेटर ड्रोन भी खरीदे हैं। भारत ने अमेरिकी सैन्य उपकरणों पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। लेकिन अमेरिकी लड़ाकू विमान नहीं खरीदे।

कारण स्पष्ट है, हालांकि इस पर खुलकर बात नहीं की जाती, वह है, युद्ध में स्वायत्तता।

एक लड़ाकू विमान सिर्फ हथियारों का मंच नहीं होता। यह किसी देश की अपनी शर्तों पर अपने आसमान की रक्षा करने की संप्रभु क्षमता का प्रतीक होता है। और जैसे ही आप अमेरिकी फाइटर जेट खरीदते हैं, यह धारणा बनती है कि आप अमेरिकी निर्भरता भी स्वीकार करते हैं-जैसे स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपग्रेड आदि में अमेरिकी निर्भरता, साथ ही निर्यात लाइसेंस, राजनीति और नीतिगत दबाव भी।

भारत ने वह भी देखा कि तुर्की के साथ हुआ, जो नाटो का सदस्य है और एफ-16 उड़ाता है, अमेरिका ने द्विपक्षीय विवाद में पुर्जों की आपूर्ति रोकने की धमकी देकर दबाव बनाया। भारत ने यह भी देखा कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ-जिसके एफ-16 कई बार अमेरिका से खराब रिश्तों के कारण स्पेयर पार्ट्स की कमी से जमीन पर खड़े रह गए।

भारत ने तय किया कि वह खुद को कभी उस स्थिति में नहीं डालेगा।

जब 2000 के दशक में अमेरिका ने भारत को एफ-16 बेचने की कोशिश की, तो यह जानते हुए भी कि वही विमान पाकिस्तान को दिया जा चुका है, फिर भी उसने यह प्रस्ताव रखा। यह पेशकश कई लोगों को दुस्साहसी और अजीब लगी।

सौदा कराने के लिए लॉकहीड मार्टिन ने तो एफ-16 के एक नए संस्करण का नाम बदलकर एफ-21 तक रख दिया। यह एक मार्केटिंग चाल थी, इतनी स्पष्ट और बनावटी कि रक्षा हलकों में मज़ाक बन गई। नाम बदलो, पाकिस्तान से जुड़ी छवि मिटाओ, और सौदा कर लो-यही उम्मीद थी लेकिन भारत ने न तो वह विमान खरीदा, और न ही उस कहानी को स्वीकार किया।

कुछ साल बाद भारतीय नौसेना ने अपने विमानवाहक पोत के लिए एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट का गंभीर मूल्यांकन किया। उसने आंकड़े, तकनीकी विशेषताएं और कैरियर-अनुकूलता, सब देखा।

लेकिन जब भारतीय वायुसेना ने फ्रांस का राफेल चुना, तो नौसेना को भी वही रास्ता अपनाने का राजनीतिक आधार मिल गया। कारण तकनीकी बताए गए-जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन रणनीतिक कारण साफ थे: फ्रांस महंगा जरूर है, लेकिन सवाल नहीं पूछता।

फ्रांस शर्तें नहीं लगाता। और अगर आप रूस से पनडुब्बियां खरीदते हैं तो वह आपको दबाव में नहीं लाता।

फिर फरवरी 2019 में बालाकोट हुआ। भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी शिविर पर हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद हुई हवाई झड़प में पाकिस्तान ने एफ-16 उड़ाए और भारत ने सोवियत दौर के मिग-21 बाइसन से उनमें से एक को मार गिराया।

'अमेरिका का शत्रु होना खतरनाक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहने से वैश्विक अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और सभी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी आ जाएगी। उन्हें आशंका है कि आपूर्ति में रुकावट आने पर तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती है।

तेल आपूर्ति में लंबे समय तक रुकावट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ईरान ने होरमुज़ स्ट्रेट्स पर अपना कब्जा जमा रखा है। यह ईरान के पूर्वी तट के पास स्थित एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है, जो तेल से भरे टैंकरों की आवाजाही का मुख्य रास्ता है। होरमुज़ से लगभग 20 प्रतिशत वैश्विक तेल परिवहन होता है। होरमुज़ स्ट्रेट पर ईरान के कब्जे के साथ-साथ, अमेरिकी सहयोगी खाड़ी देशों पर ईरान के हमले भी क्षेत्र की प्रमुख तेल उत्पादन सुविधाओं को नष्ट कर रहे हैं। यह केवल खाड़ी देशों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी चिंता का विषय है।

ईरान पश्चिम एशिया के पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी देशों सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और अन्य पर अमेरिकी हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों की मेजबानी करने के कारण बमबारी कर रहा है। उनके महत्वपूर्ण ठिकानों को ईरानी मिसाइल हमलों से एक-एक कर नष्ट किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इसका उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर भारी असर पड़ेगा। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल सुविधाओं में से एक पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ है, जिससे उसे बंद करना पड़ा है। कतर के सभी गैस क्षेत्र भी बंद कर दिए गए हैं,

- **अमेरिका के युद्ध विशेषज्ञ अब महसूस करने लगे हैं, कि युद्ध क्षेत्र की इकॉनमी अब अमेरिका के खिलाफ पड़ने लगी है। उदाहरण के लिए, ईरान के ड्रोन्स व मिसाइल को रोकने के लिए काम में लिए जाने वाले अमेरिका के "इन्टरसैप्टर्स" की कीमत कई मिलियन डॉलर है, जबकि ईरान की मिसाइल की कीमत 20,000 डॉलर से भी कम है तथा ईरानी ड्रोन्स तो और भी सस्ते हैं।**
- **यही ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों में मायने रखने वाले कई देश, जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, आदि, अब संगठित होकर ट्रंप के ईरान के युद्ध के खिलाफ बोलने लगे हैं।**

क्योंकि उन्हें चालू रखना बहुत महंगा पड़ सकता है। वहीं, एक बार चालू किए गए गैस क्षेत्र को बंद करना भी अत्यंत महंगा होता है और बाद में समस्याएँ पैदा करता है। खाड़ी देशों के कई तेल टर्मिनल और बंदरगाह सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ है, जिन्हें वर्षों में भारी खर्च से दोबारा बनाना होगा। इन देशों में मिलिट्री ठिकानों पर भी ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

फिलहाल इन्हें बंद करना पड़ेगा। लेकिन इन्हें दोबारा शुरू करने के लिए मरम्मत और पुनर्निर्माण पर अरबों डॉलर खर्च करने होंगे। मौजूदा युद्ध की स्थिति में, जब रोज़मर्रा का अस्तित्व ही सबसे बड़ा सवाल है, भविष्य के ये खर्च तुरंत चिंता का विषय नहीं हैं।

इस बीच, धीरे-धीरे अमेरिकी विशेषज्ञों को एहसास हो रहा है कि युद्ध की आर्थिक स्थिति अमेरिका-इज़रायल गठजोड़ के खिलाफ जा रही है। सवाल यह है कि ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स को इन इलाकों में अमेरिकी सहयोगियों और अमेरिकी फैसिलिटीज़ पर दाग रहा है, जिन्हें रोकने के लिए बहुत महंगे इंटरसैप्टर और हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

अनुमान के अनुसार, अमेरिकी इंटरसैप्टर और मिसाइलें, जैसे पैट्रियट, कई मिलियन डॉलर की होती हैं, जबकि ईरानी मिसाइल की कीमत लगभग 20,000 डॉलर या उससे भी कम है। ईरानी ड्रोन तो इससे भी सस्ते हैं। इसलिए ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की लगातार बौछार से बचाव की लागत अमेरिका-इज़राइल गठजोड़ के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह साबित हो रही है।

दूसरी ओर, अमेरिकी विशेषज्ञ चिंतित हैं कि रक्षात्मक मिसाइलों का भंडार कम होता जा रहा है, जबकि ईरान के पास मिसाइलों का पर्याप्त भंडार है। अमेरिकी रक्षा प्रमुख डैन केन ने अभियान शुरू होने से पहले ही गोला-बारूद और मिसाइलों की कमी की चेतावनी दे दी थी, जिसे अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे डॉनल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों ने नजरअंदाज कर दिया।

ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की कुछ प्रमुख आवाज़ें ईरान में ट्रंप के युद्ध का विरोध करने वाले एक समूह के रूप में एकजुट हो रही हैं। यूरोप में स्पेन ने खुलकर अपनी बात कही है, और फ्रांस, इटली तथा अन्य देश भी बदलती स्थिति में अपने कदम मिलाने की बात कर रहे हैं।

बिहार-महाराष्ट्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया लैफ्टिनैट गवर्नर बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना भेजा गया है और तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का नया गवर्नर बनाया गया है। बिहार भाजपा के सीनियर नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया है। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का काम संभालेंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया।वहीं, भारत के राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉ. सी.वी. आनंद बोस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसकी जानकारी राष्ट्रपति भवन ने दी है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908